भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2264

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी विकास साझेदारी परियोजनाएं

2264. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

श्री अशोक कुमार रावतः

श्री मितेश पटेल बकाभाईः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत एक वर्ष के दौरान अनुदानों और ऋण सहायता के माध्यम से अनुमोदित विकास भागीदारी परियोजनाओं की संख्या और मूल्य कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत कौन–कौन से विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) विदेशी विकास परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी और परिणाम मूल्यांकन शुरू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) वर्ष 2026–27 के दौरान भारत के विकास सहयोग कार्यक्रम के लिए किन–किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ख) विगत एक वर्ष के दौरान, भागीदार देशों को लगभग 17,550 करोड़ रुपए की ऋण सहायता अनुमोदित की गई है। इन ऋण सहायताओं को अवसंरचना, कनेक्टिवटी, सामाजिक आवास और गतिशीलता, स्वास्थ्य, कृषि

और आवश्यक वस्तुओं की खरीद जैसे क्षेत्रों में विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान किया गया है।

विगत एक वर्ष के दौरान, शिक्षा, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और कनेक्टिवटी जैसे क्षेत्रों में अनुदान के तहत लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लगभग 60 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ–साथ बहुपक्षीय/बहुआयामी फ्रेमवर्क के तहत परियोजनाओं को अनुदान के रूप में अनुमोदित किया गया है।

(ग) विकास परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निगरानी और समीक्षा तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2022 से नई ई–ट्रैकिंग और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन (एनईटीआरए) पोर्टल का उपयोग ऋण सहायता संबंधी परियोजनाओं के प्रबंधन और निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय एक्सिम बैंक समय–समय पर, पूरी हो चुकी ऋण सहायता संबंधी परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन करता है।

(घ) भारत का विकास सहयोग मॉडल मांग आधारित है और यह भागीदार देशों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर आधारित है।

****